International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 4 Issue 2, March-April, 2016, Impact Factor: 1.554

राजस्थान में शहरीकरण का विकास एवं नगरपालिकाओं की सांगठनिक और प्रबंधकीय समस्याएँ (झुंझुनू एवं सीकर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

सुभाष चन्द्र सैनी

शोधछात्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

शोध सारांशः

राजस्थान में गत कुछ दशकों में शहरीकरण की गति तीव्र हुई है, जिससे राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। झुंझुनू एवं सीकर जैसे जिले, जो कभी मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र माने जाते थे, अब शहरी विकास की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में नगरपालिकाओं की भूमिका केंद्र में आ गई है, परंतु इन संस्थाओं को सांगठनिक जटिलताओं, सीमित संसाधनों, दक्ष मानव बल की कमी और प्रबंधकीय अक्षम्यताओं जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह शोध–लेख झुंझुनू और सीकर जिलों के विशेष संदर्भ में शहरीकरण के प्रभावों और नगरपालिकाओं की वर्तमान चुनौतियों का विश्लेषण करता है तथा उनके प्रभावी समाधान की संभावनाओं पर विचार प्रस्तुत करता है।

प्रस्तावनाः

राजस्थान, जो ऐतिहासिक रूप से एक ग्रामीण और परंपरागत जीवनशैली वाला राज्य माना जाता है, अब तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। औद्योगीकरण, शिक्षा, और बेहतर आधारभूत संरचना जैसे कारकों के कारण राज्य के कई जिलों में जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन हुआ है। झुंझुनू और सीकर जैसे जिले, जो लंबे समय तक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहे, अब अर्ध–शहरी और शहरी स्वरूप धारण कर रहे हैं। इस बदलाव के साथ ही नगरपालिकाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन साथ ही उन्हें अनेक सांगठनिक और प्रबंधकीय समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। शहरी विकास को सुचारू और संतुलित बनाए रखने के लिए इन स्थानीय शासकीय निकायों की क्षमता, संरचना और कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन आवश्यक हो गया है।

शहरीकरण की वर्तमान स्थितिः

राजस्थान में शहरीकरण की प्रक्रिया धीरे–धीरे बढ़ रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की कुल जनसंख्या का 24.87% शहरी क्षेत्रों में निवास करता था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 31.1% था। हालांकि, यह अनुमान लगाया गया है कि 2021 तक राजस्थान की शहरी जनसंख्या बढ़कर 26.33% हो गई होगी। राज्य में शहरीकरण की दर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन कुछ जिलों में यह अधिक स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, कोटा (60.31%), जयपुर (52.40%), और अजमेर (40.08%) जैसे जिले सबसे अधिक शहरीकृत हैं, जबकि डूंगरपुर (6.39%), बाड़मेर (6.98%), और बांसवाड़ा (7.10%) जैसे जिले सबसे कम शहरीकृत माने जाते हैं। झुंझुनू और सीकर जिलों में भी शहरीकरण की प्रवृत्ति देखी गई है, हालांकि ये जिले अभी भी अपेक्षाकृत कम शहरीकृत हैं। सीकर जिले की कुल जनसंख्या 2011 में लगभग 26.77 लाख थी, जिसमें से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत राज्य के औसत से कम था। इन जिलों में शहरीकरण की गति धीमी होने के बावजूद, शिक्षा और

औद्योगीकरण जैसे कारकों के कारण शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास बढ़ रहा है, जिससे नगरपालिकाओं पर दबाव बढ़ रहा है और उन्हें विभिन्न सांगठनिक और प्रबंधकीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।.

नगरपालिकाओं की भूमिका

नगरपालिकाएँ शहरी क्षेत्रों के स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना और शहरी विकास को सुचारु रूप से संचालित करना है। इनके कार्यों में स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, और मनोरंजन जैसी सेवाएँ शामिल हैं। नगरपालिकाएँ शहरी नियोजन, भवन निर्माण अनुज्ञा, और पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका गठन संविधान के 74वें संशोधन (1992) के तहत किया गया है, जो शहरी स्थानीय निकायों को स्वशासन की शक्ति प्रदान करता है। नगरपालिकाएँ नागरिकों की भागीदारी से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाती हैं और उनके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होती हैं। इस प्रकार, नगरपालिकाएँ शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

नगरपालिकाओं की सांगठनिक समस्याएँः

राजस्थान की नगरपालिकाओं को कई सांगठनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी कार्यक्षमता और सेवा वितरण को प्रभावित करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रशिक्षित और पर्याप्त मानव संसाधन की कमी, कार्यों और जिम्मेदारियों का अस्पष्ट विभाजन, तकनीकी दक्षता का अभाव, और निर्णय–निर्माण प्रक्रियाओं में अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। इन समस्याओं के कारण नगरपालिकाओं की संचालन क्षमता प्रभावित होती है, जिससे शहरी विकास और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनकी मुख्य सांगठनिक समस्याओं को निम्न बिन्दूओं के अर्न्तगत बतलाया जा सकता हैं।

- कर्मचारियों की कमीः अधिकांश नगरपालिकाओं में प्रशिक्षित व पर्याप्त मानव संसाधन की कमी है।
- अस्पष्ट कार्य–विभाजनः जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं होने से कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
- तकनीकी ज्ञान का अभावः डिजिटल भारत की दिशा में कार्य करते हुए भी कई कर्मचारी तकनीकी रूप से दक्ष नहीं हैं।
- राजनीतिक हस्तक्षेपः नगरपालिकाओं के कार्यों में अनावश्यक राजनीतिक दखल से निर्णय लेने की प्रक्रिया
- बाधित होती है।

प्रबंधकीय समस्याएँः

राजस्थान की नगरपालिकाएँ विभिन्न प्रबंधकीय चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जो उनकी कार्यक्षमता और सेवा वितरण को प्रभावित करती हैं। इनमें प्रमुख रूप से वित्तीय संसाधनों की कमी, बजट आवंटन में असंगति, योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी, और निगरानी तथा पारदर्शिता की कमी शामिल हैं। स्थानीय करों और राजस्व स्रोतों का सीमित होना वित्तीय स्वायत्तता में बाधा डालता है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त, बजट का अनुचित आवंटन और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी से नागरिकों में असंतोष बढ़ता है। निगरानी तंत्र की कमजोरियाँ और पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे नगरपालिकाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। इन प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान के लिए वित्तीय प्रबंधन में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने, और प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है। इनकी मुख्य प्रबंधकीय समस्याओं को निम्न बिन्दूओं के अर्न्तगत बतलाया जा सकता हैं।

- वित्तीय संसाधनों की कमीः नगरपालिकाओं के पास स्वतंत्र राजस्व के सीमित साधन हैं।
- अनुचित बजट आवंटनः योजनाएं तो बनती हैं पर उन्हें लागू करने हेतु वित्तीय प्रबंधन की कमी होती है।
- योजना कार्यान्वयन में देरीः योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर नहीं हो पाता, जिससे जनता में असंतोष रहता है।

- निगरानी और पारदर्शिता का अभावः निगरानी तंत्र की कमजोरियाँ और पारदर्शिता की कमी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।

झुंझुनूं एवं सीकर जिले की विशेष स्थितिः

झुंझुनू और सीकर जिले राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में स्थित हैं और शहरीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन देख रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, झुंझुनू जिले की कुल जनसंख्या 21,37,045 थी, जिसमें से 4,89,079 लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते थे, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22.89% है सीकर जिले की कुल जनसंख्या 26,77,333 थी, जिसमें से शहरी आबादी 2,44,497 थी, जो लगभग 9.13% है इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि दोनों जिलों में शहरीकरण की प्रक्रिया जारी है, हालांकि सीकर जिले में शहरीकरण की दर अपेक्षाकृत कम है।

शहरीकरण के इस बढ़ते प्रभाव के बावजूद, दोनों जिलों की नगरपालिकाओं को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें बुनियादी ढांचे की कमी, वित्तीय संसाधनों की सीमितता, और कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता प्रमुख हैं विशेष रूप से, सीकर शहर कोचिंग हब के रूप में उभर रहा है, जिससे छात्र समुदाय की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इसके साथ ही नगरपालिकाओं पर अतिरिक्त दबाव भी बढ़ा है इसलिए, इन जिलों में नगरपालिकाओं की सांगठनिक और प्रबंधकीय क्षमताओं को मजबूत करना आवश्यक है ताकि शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके और नागरिकों को बेहतर सेवाएँ प्रदान की जा सकें। संक्षिप्त मे यह कहा जा सकता है कि

- दोनों जिले शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हैं, जिससे शहरीकरण को गति मिली है।
- हालाँकि आधारभूत ढाँचे की दृष्टि से नगरपालिकाएँ अभी भी पीछे हैं।
- सीकर में स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए प्रयास हो रहे हैं, जबकि झुंझुनू में भी कुछ हिस्सों को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- फिर भी नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में भारी अंतर और असमानता देखी जाती है।

समाधान एवं सुझावः

उपरोक्त समस्याओ के समाधान के लिए एक प्रभावी रणनीति बनाकर उस पर काम किया जाना आवश्यक है सामान्य रूप से इसके लिए निम्न उपाय काम मे लिए जाकर इसे और अधिक त्वरण के साथ कार्य करने वाली इकाईयों मे बदला जा सकता है।

- क्षमता विकासः कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान बढ़ाना।
- वित्तीय स्वायत्तताः स्थानीय करों और संसाधनों के माध्यम से वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ाना।
- डिजिटल गवर्नेंसः नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्ज् आधारित प्रणाली अपनाना।
- सार्वजनिक सहभागिताः नागरिकों को योजना निर्माण और निगरानी में शामिल करना।
- स्थानीय नेतृत्व को सशक्त बनानाः निर्वाचित प्रतिनिधियों को अधिकार और संसाधन देना।

निष्कर्षः

राजस्थान में शहरीकरण का बढ़ता प्रभाव झुंझुनू और सीकर जैसे जिलों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इस परिवर्तन के साथ नगरपालिकाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। परन्तु वर्तमान में ये संस्थाएँ अनेक सांगठनिक और प्रबंधकीय समस्याओं से जूझ रही हैं। यदि इन समस्याओं का समाधान योजनाबद्ध एवं सशक्त तरीके से किया जाए, तो न केवल इन जिलों का बल्कि सम्पूर्ण राज्य का शहरी विकास एक उदाहरण बन सकता है।

संदर्भ ग्रन्थसूचीः

- भारत सरकार, जनगणना रिपोर्ट 2011
- राजस्थान शहरी विकास निदेशालय की वार्षिक रिपोर्ट2011–2014
- झुंझुनू एवं सीकर नगरपालिकाओं की वेबसाइट्स एवं प्रगति रिपोर्ट 2011–2015
- विभिन्न शोध पत्र व शहरी अध्ययन रिपोर्ट्स